श्रीमती ऊषा वर्मा (खीरी) : मान्यवर, मैं इस सभा का ध्यान उत्तर प्रदेश के शारदा सहायक परियोजना की ओर दिलाना चाहती हूं। यह परियोजना भारत की सब से बड़ी परियोजना है। इसका प्रारम्भ जनपद लखीमपुर-खीरी उत्तर प्रदेश की घाघरा तथा शारदा नदियों को योजक नहर द्वारा जोड़कर किया गया है और इससे लगभग 45 लाख एकड़ भूमि सींचने का प्रावधान है और जो सन 1976 से सिचाई शुरू करके अब पूर्ण रूप से सिंचाई क्षमता प्राप्त कर ली है।

परन्तु खेद है कि इस परियोजना से जहां लाखों लोगों को सिचाई उपलब्ध हुई है वहीं हजारों लोगों को इस परियोजना के रिसन से अपार कष्ट है। फिर भी सरकार उनसे लगान वसूल करती जाती है जब कि अतिवृष्टि या बाढ़ से फसल नष्ट होने पर सभी को अहेतुक सहायता दी जाती है और उनका लगान भी माफ़ किया जाता है। यही नहीं हमारे जनपद खीरी की योजक और पोषक नहर के रिसन से बहुत से ग्रामों में हर समय पानी भरा रहता है जिससे हजारों लोगों के मकान ध्वस्त हो गये हैं और होते जा रहे हैं। इस सीपेज के पानी से क्षेत्र के प्राकृतिक नालों एवं खलोज में पानी भर जाने से तमाम रास्ते अवरुद्ध हो गये हैं और इनको जाड़ों में पार करते करते हजारों लोग अपंग हो गये हैं तथा जानवर भी अपंग हो कर बेकार हो गये तथा इस पानी में कई प्रकार की जहरीली घास पैदा हो गई है जिसको खा कर मरते जा रहे हैं।

श्रीमान जो कच्ची नालियां बनाई जाती हैं, उनसे पानी निकलता ही नहीं क्योंकि एक तरफ वह खोदी जाती हैं दूसरी तरफ़ उनमें मिट्टी भर जाने से पानी का बहाव रुक जाता है तथा इन नालियों में घास उग आने से भी पानी का बहाव रुक जाता है।

अतः मेरा जनहित में निम्न सुझाव है कि इस परियोजना से 45 लाख एकड़ भूमि सिंचित का जो लक्ष्य था वह एक तिहाई पानी सीपेज में चले जाने से लक्ष्य पूर्ति नहीं हो पा रही है। अतः इस परियोजना की योजक नहर घाघरा से शारदा तक, जो केवल 29 किलोमीटर है, को अन्दर से पक्की करा दिया जाय। इसके पश्चात पोषक नहर भी धीरे धीरे पक्की करा दी जाय। इसमें जितना खर्च आवेगा उससे लगभग 15 लाख एकड़ सिंचन क्षमता की अन्य परियोजना पर कहीं अधिक खर्च करना पड़ेगा। इससे एक तरफ सीपेज को समस्या हल होगी और अतिरिक्त 15 लाख एकड़ की क्षमता बढ़ेगी। अभी तक जितने कृषकों को भूमि सीपेज से प्रभावित हुई है उनका पूरा लगान तथा फसल का मुआवजा दिलाया जाय।

अतः उपरोक्त क्षेत्र में उन सभी नाले, नदी और बांधों पर जहां जहां सीपज से मार्ग अवरुद्ध हुए हैं पुल तथा पुलिया सिंचाई विभाग द्वारा बनवाये जायें।

मैं इस लोक महत्व का प्रश्न कर के अवगत कराना चहती हूं कि भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार उपरोक्त कार्य शीघ्र कराकर प्रधान मंत्री के बीस सूत्री कार्यक्रम का सही अर्थों में क्रियान्वयन होगा।

(iv) OPENING OF REGIONAL DEFENCE COLLEGES.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : मान्यवर, देश के 18 सैनिक स्कूलों में शिक्षा दे कर हम देश के भावी सीमा प्रहरियों को तैयार करते हैं। रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त राज्य सरकारों को प्रति बच्चे पर लगभग 30 हजार रु०

[प्रो निर्मला कुमारी शक्तावत]

शुरू से आखिर तक व्यय करने पड़ते हैं । पर इस व्यय का पूरा उपयोग नहीं होता क्योंकि सैनिक स्कूलों में शिक्षा प्राप्त 70 प्रतिशत विद्यार्थी एन० डी० ए० में पास नहीं हो पाते । अतः वह सभी बच्चे सामान्य स्कूलों के बच्चों के समान दूसरे कालेजों में भटकते हैं और इन पर किया गया सारा खर्चा व्यर्थ हो जाता है । अतः मैं रक्षा मंत्री जी से पुरजोर शब्दों में निवेदन करूंगी कि देश में नये 5 रीजनल सैनिक कालेज बनें । उनमें से एक राजस्थान में भी हो क्योंकि यह वीरों की भूमि रही है ।

इन सैनिक कालेजों का बनाने में सरकार का बहुत अधिक खर्चा भी नहीं होगा क्योंकि सैनिक स्कूलों के पास पर्याप्त भूमि है जहां इन्हें बनाया जा सकता है । विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई तथा रहने का खर्चा करने के बाद यू० जी० सी० द्वारा प्रदत्त राशि से इन सैनिक कालेजों को चलाया जा सकता है । ऐसे रीजनल सैनिक कालेजों के बनने से सरकार सैनिक स्कूल से निकले विद्यार्थियों पर किये गये व्यय का सदुपयोग कर सकेगी । विद्यार्थी स्नातक स्तर तक सैनिक शिक्षा लेने के बाद किसी भी जल, थल और नभ रक्षा सेवा के लिए तैयार हो जायेंगे । एन० डी० ए० के अतिरिक्त अन्य ओ० टी० एस०; आई० एम० ए० या अन्य रक्षा सेवा में जा सकेंगे ।

MR. DEPUTY SPEAKER: Shri Mool Chand Daga and Shri Girdhari Lal Vyas support i.

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : यहां से शिक्षा प्राप्त व्यक्ति रक्षा सेवा में नहीं जा सके, वह सैनिक स्कूलों के लिए अच्छे व्याख्याता भी बन सकेंगे । अतः रीजनल सैनिक कालेज की योजना पर सरकार ध्यान दे ।

(v) FINANCIAL ASSISTANCE TO PRISONERS RELEASED RECENTLY FROM PAKISTAN JAILS

SHRI A. K. BALAN (Ottapalam): Mr. Deputy-Speaker, Sir, it is a matter of great relief and satisfaction that ten prisoners who were in the Pakistan jails for the last few years are at least released.

I had visited the psychiatric ward of Dr. Ram Manohar Lohia Hospital where they are put up.

Some of them have lost their mental balance and require psychiatric treatment. But five of them are quite normal and there is no need of keeping them in psychiatric ward which is already declared by medical authorities. Out of these, there are three people from Kerala who are from my constituency and nearby area. They are Mr. Neehikkatial Hyder of Vilayoor, Mr. Poonthiruthi Sivaraman of Irumbilassery (Ottappalam) and Mohammed Chembakabssery of Edakkara, Nilanbur. I had a detailed discussion with them and they disclosed me that they are very eager to meet their aged mothers and relatives whom they have not met for years. They come from very poor families and hence their relatives are not in a position to come to Delhi and receive them.

I take this opportunity to request the Government through you, Sir, to make all arrangements and meet the expenses so that they can reach Kerala without any delay and fulfil their long desire of meeting their relatives.

MR. DEPUTY SPEAKER: I also recommend this case to the Railway Minister. He will make the arrangement.

(vi) SETTING UP OF A FERTILIZER UNIT IN CENTRAL SECTOR AT SAWAI MADHOPUR IN RAJASTHAN

SHRI KRISHNA KUMAR GOYAL (Kota): Sir, a proposal to set up a fertiliser complex in the Central Sec-